भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2903 का उत्तर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास

2903. श्री अनुराग शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो पूरी हो चुकी और चालू पूर्वी तथा पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य प्रस्तावित कॉरिडोरों की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान डीएफसी परियोजनाओं के लिए आबंटित, जारी और उपयोग किए गए धन का ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार कितनी भौतिक प्रगति प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सरकार ने माल ढुलाई, संभारतंत्र लागत, यात्री रेल मार्गों की भीड़भाड़ कम करने और औद्योगिक विकास पर डीएफसी के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशभर में मल्टीमॉडल संभारतंत्र, आर्थिक विकास और उन्नत माल ढुलाई क्षमता की सहायता करने के लिए शेष कार्यों में तेजी लाने और डीएफसी नेटवर्क का विस्तार करने के वास्ते सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल मंत्रालय ने 1,24,005 करोड़ रु. की लागत से दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यथा लुधियाना से सोननगर तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1337 कि.मी.) और दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1506 कि.मी.) का निर्माण कार्य शुरू किया है। दोनों डीएफसी अर्थात ईस्टर्न डीएफसी (1337 कि.मी.) और वेस्टर्न डीएफसी (1506 कि.मी.) को पूरा और कमीशन कर दिया गया है।

डीएफसी के पूरे किए गए कार्य को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	**पूरे किए गए कार्य़ (मार्ग कि.मी.)**
2014 तक	**शून्य**
2014 से 2026 (मार्च 2026 तक)	**2843**

औसतन डीएफसी पर प्रतिदिन लगभग 443 गाड़ियां परिचालित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, डीएफसी नेटवर्क पर कुल 1,47,993 मालगाड़ियाँ परिचालित की गईं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने सुदृढ़ परिचालन कार्य निष्पादन का प्रदर्शन किया है। उच्चतर औसत गति, तीव्रतर टर्नअराउण और विश्वसनीयता में वृद्धि होने से माल ढुलाई की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल यातायात को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ओर मोड़कर पारंपरिक नेटवर्क पर अतिरिक्त मार्ग सृजित करने में मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप, रेलवे को अपने नेटवर्क पर अतिरिक्त माल और कोचिंग सेवाओं के परिचालन में सफलता मिली है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना से देश भर में लागत प्रभावी, कुशल और संवहनीय माल ढुलाई हो सकने के कारण रेल परिवहन की प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ होने की आशा है। लंबी दूरी के थोक पण्यों, कंटेनर यातायात और औद्योगिक माल ढुलाई को सड़क से रेल में क्रमिक रूप से मॉडल शिफ्ट करने की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिससे समग्र संभार-तंत्र लागत में कमी आएगी, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार होगा और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

भारतीय रेल में माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए, 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है। जीसीटी के स्थान के लिए उद्योग की मांग, कार्गो यातायात की क्षमता, रेल अवसंरचना की उपलब्धता और क्षेत्र की समग्र संभार-तंत्र क्षमता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

अब तक, 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) (डीएफसीसीआईएल कॉरिडोरों पर 7 सहित) को कमीशन किया गया है। इसके अलावा, 310 अन्य स्थानों पर जीसीटी के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) प्रदान किया गया है। चालू किए गए 142 जीसीटी की अनुमानित माल सम्हलाई क्षमता 224 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इस नीति के माध्यम से इन

जीसीटी में लगभग ₹10,000 करोड़ का निजी निवेश जुटाया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान इन जीसीटी पर 146 मिलियन टन माल की सम्हलाई की गई।

केंद्रीय बजट 2026 में, पूर्व में डानकुनि को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इस कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने/अद्यतन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना की कुल लागत, वित्तपोषण तंत्र, समय-सीमा आदि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद बताया जा सकता है।

परियोजना को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए, परियोजना को पहले से ही "विशेष रेल परियोजना" घोषित किया गया है। कुल 34 जिलों में से 30 जिलों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) का नामांकन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया गया है और राज्य सरकार के साथ समन्वय के लिए डीएफसीसीआईएल द्वारा 07 स्थानों (सूरत, जलगाँव, नागपुर, रायपुर, झारसुगुड़ा, टाटा नगर और कोलकाता) पर समर्पित टीमें तैनात की गई हैं।

******